



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 236 राँची, शुक्रवार 2 ज्येष्ठ 1936 (श०)
23 मई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

22 मई, 2014

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 196/गो०, दिनांक 18.02.2013, पत्रांक 5/आ०, दिनांक 21.01.2011 एवं पत्रांक-112/स्था०, दिनांक 05.03.2014
2. प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 6406, दिनांक 30.11.2010
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू का पत्रांक- 275, दिनांक 04.04.2013
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2362, दिनांक 3.03.2013

संख्या-5/आरोप-1-653/2014 का.- 4574-- श्री सागर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-921/03, गृह जिला- गुमला) के विरुद्ध इनके प्रखंड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 196/गो०, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ में प्राप्त है। श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 6406, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 से प्राप्त निदेश के आलोक में अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार के बीच खाद्यान्न के वितरण हेतु उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 5/आ0, दिनांक 21 जनवरी, 2011 से प्रखण्ड स्तर पर प्रभारी अनुश्रवण के लिए आपको नामित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा कभी भी इस विषयक वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कोई अनुश्रवण/निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा उपायुक्त, पलामू को किसी प्रकार की अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदन ही प्रेषित किया गया। आपके द्वारा अगर उपरोक्त दिए गए निदेश का अनुपालन सही ढंग से किया जाता तो छत्तरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अनाज के उठाव एवं वितरण में अनियमितता की संभावना नहीं रहती। इससे यह प्रतीत होता है कि आपने अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती है।

2. आपने उच्चाधिकारियों के द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना की है।

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर होने के नाते आपका यह दायित्व बनता था कि पूरे प्रखंड क्षेत्र अन्तर्गत जन-वितरण प्रणाली की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहते एवं निरीक्षण टिप्पणी से उपायुक्त, पलामू को अवगत कराते रहते तो इस तरह की अनाज की कालाबजारी की संभावना नहीं रहती। इससे यह प्रतीत होता है कि आपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं किया है।

4. सभी जन-वितरण प्रणाली की दुकानदारों के बीच अतिरिक्त बी0पी0एल0 की चावल वितरण के लिए पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया था। पंजी में प्रत्येक माह वितरित किए गए चावल की मात्रा अंकित करते हुए उपभोक्ता का हस्ताक्षर कराना था। आपके द्वारा जन-वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण नहीं करने के फलस्वरूप दुकानदारों द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-2362, दिनांक 13 मार्च, 2013 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा विभागीय निदेश के अनुपालन में अपना स्पष्टीकरण पत्रांक- 275, दिनांक 4 अप्रैल, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है।

उपायुक्त, पलामू द्वारा पत्रांक-112/स्था0, दिनांक 5 मार्च, 2014 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर अपना मन्तव्य उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त, पलामू ने उपर्युक्त आरोप संख्या-3 को छोड़कर शेष आरोपों के लिए श्री कुमार के स्पष्टीकरण को तार्किक माना है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री कुमार को आरोप सं0-3 के लिए प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के असहयोगात्मक व्यवहार के बारे में उच्चाधिकारियों को जानकारी नहीं देने के लिए दोषी पाया गया है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित उक्त आरोप के लिए इन पर 'निन्दन' दण्ड अधिरोपित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।
